

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 29-08-25



The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Friday, 29 Aug, 2025

Edition: International Table of Contents

Page 04 Syllabus :GS 2 : Indian Polity / Prelims	तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, राज्यपाल 'सुपर सीएम' की तरह काम नहीं कर सकते
Page 06 Syllabus : GS 2 : Social Justice / Prelims	3-11 आयु वर्ग में स्कूल नामांकन में 25 लाख की कमी: यूडीआईएसई+
Page 07 Syllabus : GS 3 : Science & Technology / Prelims	विज्ञान कथा से परे: कृत्रिम गर्भाशय और प्रजनन उपचारों की वास्तविक प्रगति
Page 08 Syllabus :GS 2 : Social Justice / Prelims	1.4 अरब भारतीयों के लिए स्वास्थ्य का निर्माण
Page 10 Syllabus :GS 3 : Indian Economy / Prelims	कौन से क्षेत्र टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं?
Page 08 : Editorial Analysis Syllabus :GS 1 : Indian Society	भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक टाइम बम के रूप में

राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच चल रही खींचतान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। तमिलनाडु ने वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी के माध्यम से तर्क दिया कि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं, विधायी प्रक्रिया में एक "सुविधाकर्ता" हैं, लेकिन एक समानांतर राजनीतिक प्राधिकारी या "सुपर मुख्यमंत्री" नहीं हैं। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल, 2025 के फैसले के बाद राष्ट्रपति के संदर्भ के संदर्भ में उठा है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपालों के लिए विधेयकों के निपटारे की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

Governor cannot act as 'super CM', Tamil Nadu tells Supreme Court

The Governor is at best a 'lubricator' or 'facilitator' but not a legislator, says Tamil Nadu's counsel A.M. Singhvi; how can Governor be interpreted as having the last word on a Bill, he asks a Presidential Reference Bench headed by CJI Gavai

Krishnadas Rajagopal
NEW DELHI

The State of Tamil Nadu on Thursday countered in the Supreme Court the version of the Centre and BJP-ruled States that gubernatorial discretion is "wide", saying a Governor cannot act as "super Chief Minister" and there cannot be "two swords in the same scabbard".

Appearing before a Presidential Reference Bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai, senior advocate A.M. Singhvi said the Governor is at best a "lubricator", a "facilitator", but not a legislator.

Tamil Nadu argued that a Chief Minister and his Cabinet must, in the best interest of democracy and the parliamentary form of governance, be responsible for the good governance of a State.

"A Governor is a part of the legislative process, but



Court proceedings: A.M. Singhvi argues before a Bench headed by Chief Justice of India B.R. Gavai. [YOUTUBE@SUPREMECOURTOFINDIA](https://www.youtube.com/watch?v=...)

he is not part of the legislation of the State. He is not a legislator. He may have a role in the legislative process, but that too on the aid and advice of the Council of Ministers," Mr. Singhvi submitted.

He referred to the submissions raised by the Centre and States supporting the Presidential Reference, which has raised questions about the time limits prescribed by the apex court in an April 8, 2025 judgment in the Ta-

mil Nadu Governor case, noting that many doomsday scenarios were portrayed if the Governor's discretion under Article 200 (assent to State Bills) was curtailed.

"Hypothetically anything may happen. The sky may fall on our heads. Constitutional interpretations cannot be done in the backdrop of doomsday predictions... A Governor cannot have a dominating role over the State executive or legislature," Mr.

Singhvi said. Tamil Nadu asked the Bench how a Governor could be interpreted as having the last word on a Bill.

"The power to assent, withhold, return Bills by the Governor is only to facilitate law-making in the State... In responsible governments, there is no room for the 'general' discretion of the Governor... General discretion to Governor would create chaos," Mr. Singhvi contended.

He said a Governor's discretion to return a Bill to the Assembly or refer to the President were both guided by the State Cabinet.

"There would be situations in which the government would want a rethink. There could be a change of policy – all these are possibilities for the Governor to return the Bill to the Assembly. There may be cases where the government itself knows the Bill

requires Presidential assent or the government is in doubt, then Governor may refer it to the President," Mr. Singhvi explained.

Solicitor-General Tushar Mehta, for the Centre, made additional submissions on the question whether a State could move the top court under Article 32 complaining of violation of its fundamental rights by the Governor.

"A State is the bearer of constitutional duties, not the holder of fundamental rights. Therefore, a State cannot maintain a petition under Article 32 on the footing that its own fundamental rights have been infringed. A State cannot use Article 32 to litigate fundamental rights in a representative capacity," Mr. Mehta argued.

He also submitted that a Governor enjoyed "complete immunity" under Article 361 for his performance in office.

चर्चा के प्रमुख मुद्दे

1. कानून निर्माण में राज्यपाल की भूमिका

- तमिलनाडु ने इस बात पर ज़ोर दिया कि राज्यपाल विधायी प्रक्रिया का एक हिस्सा तो हैं, लेकिन वे विधायक नहीं हैं।
- उनकी भूमिका मंत्रिपरिषद (अनुच्छेद 163 और 200) की सहायता और सलाह से बंधी है।

2. लोकतांत्रिक जवाबदेही

- संसदीय लोकतंत्र में, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सीधे विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
- राज्यपाल को "सामान्य विवेकाधिकार" देने से प्रतिनिधि लोकतंत्र कमज़ोर होगा और "एक ही म्यान में दो तलवारें" बनेंगी।

3. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ

- राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार लौटा सकते हैं या राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार ही किया जाना चाहिए।
- राज्य की शक्ति के दुरुपयोग ("प्रलय के दिन की परिस्थितियाँ") की काल्पनिक आशंकाएँ राज्यपाल के विवेकाधिकार के विस्तार को उचित नहीं ठहरा सकतीं।

4. केंद्र का प्रतिवाद

- सॉलिसिटर-जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि राज्य राज्यपालों के विरुद्ध अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि राज्यों के पास मौलिक अधिकार नहीं हैं, केवल संवैधानिक कर्तव्य हैं।
- राज्यपालों को पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए अनुच्छेद 361 के तहत पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है।

संवैधानिक और राजनीतिक महत्व

- संघीय संतुलन: यह मामला राज्यपाल के अधिकार को लेकर केंद्र और राज्यों के बीच, विशेष रूप से विपक्ष शासित राज्यों में, बार-बार होने वाले तनाव को उजागर करता है।
- न्यायिक स्पष्टीकरण: राज्यपालों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर और मंत्रिमंडल की सलाह पर सख्ती से कार्य करना चाहिए या नहीं, इस बारे में न्यायालय का निर्णय केंद्र-राज्य संबंधों को आकार देगा।
- लोकतांत्रिक मानदंड: राज्यपाल के सीमित विवेकाधिकार को बनाए रखना, मनोनीत प्रमुखों पर निर्वाचित सरकारों की प्रधानता को पुष्ट करता है।

निष्कर्ष

- यह बहस भारतीय संघवाद के एक मूलभूत प्रश्न को रेखांकित करती है: क्या राज्यपालों को विधायी प्रक्रिया के तटस्थ सूत्रधार के रूप में कार्य करना चाहिए या स्वतंत्र विवेक वाले सत्ता-केंद्र के रूप में। तमिलनाडु का तर्क संसदीय लोकतंत्र की भावना की पुष्टि करता है, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। "सुपर-सीएम" प्रवृत्तियों को प्रतिबंधित करने वाला एक स्पष्ट न्यायिक निर्णय सहकारी संघवाद और संवैधानिक नैतिकता को मज़बूत करेगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 निम्नलिखित से संबंधित है:

- (a) कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान
- (b) राष्ट्रपति और राज्यपालों की उन्मुक्तियाँ
- (c) मंत्रिपरिषद के कार्य
- (d) विधेयकों पर स्वीकृति

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: "राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख हैं, न कि कोई 'सुपर मुख्यमंत्री'।" हाल की न्यायिक बहसों के आलोक में, अनुच्छेद 163 और 200 के अंतर्गत राज्यपालों की संवैधानिक स्थिति और विवेकाधिकार का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (250 Words)

Page 06:GS 2 : Social Justice / Prelims

शिक्षा मंत्रालय के यूडीआईएसई+ 2024-25 के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023-24 की तुलना में, प्री-प्राइमरी से कक्षा 5 तक, 3-11 आयु वर्ग के लगभग 25 लाख छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। कक्षा 1-12 तक कुल नामांकन भी घटकर 24.69 करोड़ रह गया है, जो 2018-19 के बाद से सबसे कम है। हालाँकि यह घटती प्रजनन दर जैसे जनसांख्यिकीय बदलावों को दर्शाता है, लेकिन यह डेटा भारत में बदलते शैक्षिक पैटर्न की भी जानकारी देता है।

मुख्य निष्कर्ष

1. प्रारंभिक चरण के नामांकन में गिरावट

- आधारभूत और प्रारंभिक चरण के नामांकन 12.09 करोड़ (2023-24) से घटकर 11.84 करोड़ (2024-25) हो गए।
- प्राथमिक कारक: घटती जन्म दर (भारत का कुल प्रजनन दर = 1.91, प्रतिस्थापन स्तर से नीचे)।
- बच्चों का स्वतंत्र निजी प्री-प्राइमरी संस्थानों में प्रवास भी इसमें योगदान देता है।

2. समग्र नामांकन रुझान

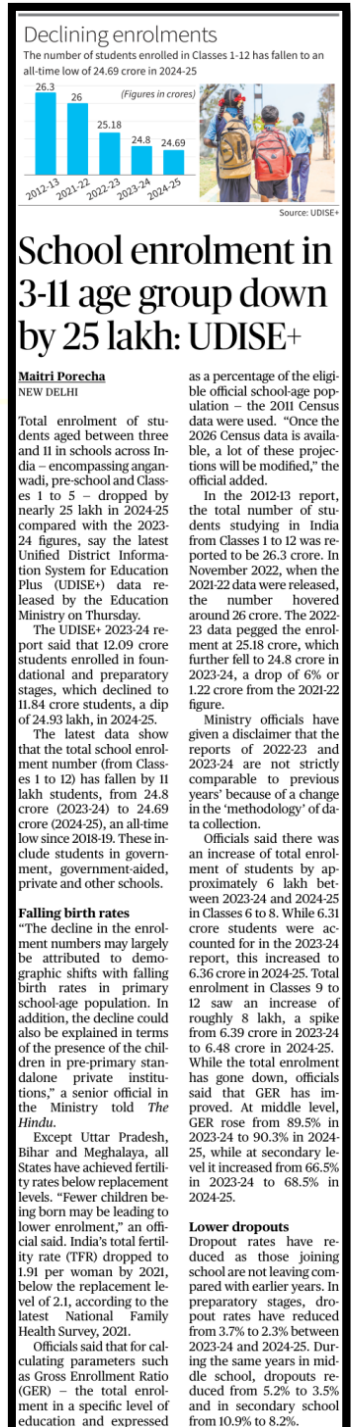
- कक्षा 1-12 में कुल नामांकन 2024-25 में 11 लाख कम हो गया।
- दीर्घकालिक रुझान: 26.3 करोड़ (2012-13) से अब 24.69 करोड़ (एक दशक में लगभग 1.6 करोड़ की गिरावट)।

3. उच्च कक्षाओं में विपरीत लाभ

- कक्षा 6-8 में नामांकन 6 लाख और कक्षा 9-12 में 8 लाख बढ़ा।
- बच्चों के उच्च कक्षाओं में जाने के साथ बेहतर प्रतिधारण और संक्रमण दर का संकेत देता है।

4. जीईआर (सकल नामांकन अनुपात) में सुधार

- मध्य स्तर जीईआर: 89.5% → 90.3%।
- माध्यमिक स्तर जीईआर: 66.5% → 68.5%।
- यह दर्शाता है कि यद्यपि पूर्ण नामांकन में गिरावट आई है, स्कूल में आयु-योग्य बच्चों का अनुपात बढ़ा है।



5. स्कूल छोड़ने की दर में गिरावट

- प्रारंभिक चरण: 3.7% → 2.3%
- मिडिल स्कूल: 5.2% → 3.5%
- माध्यमिक विद्यालय: 10.9% → 8.2%
- नामांकित छात्रों को प्रणाली के भीतर बनाए रखने में अधिक सफलता दर्शाता है।

गिरावट के कारण

- जनसांख्यिकीय बदलाव: उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय को छोड़कर अधिकांश राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट।
- निजी प्री-स्कूल: औपचारिक स्कूल डेटा के बाहर प्रारंभिक बचपन की शिक्षा का बढ़ता हिस्सा।
- डेटा पद्धति: 2022 के बाद UDISE+ रिपोर्टिंग विधियों में बदलाव से तुलनात्मकता प्रभावित हो रही है।

नीति के निहितार्थ

1. शिक्षा योजना और बुनियादी ढाँचा: प्रारंभिक वर्षों में नामांकन में गिरावट के कारण कुछ राज्यों में स्कूल के बुनियादी ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता हो सकती है।
2. गुणवत्ता पर ध्यान: कम बच्चों के साथ, सीखने के परिणामों और शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जाना चाहिए।
3. पूर्व-प्राथमिक विनियमन: निजी स्वतंत्र पूर्व-विद्यालयों को औपचारिक रिपोर्टिंग ढाँचों में एकीकृत करने की आवश्यकता।
4. जनसांख्यिकीय लाभांश: घटती बाल जनसंख्या भविष्य में कार्यबल के घटने का संकेत देती है; उत्पादकता बनाए रखने के लिए नीति को शिक्षा को कौशल विकास के साथ जोड़ना होगा।
5. जनगणना अद्यतन: वर्तमान जीईआर गणना पुरानी 2011 की जनगणना पर आधारित है, 2026 की जनगणना के नए आंकड़ों की तत्काल आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- यूडीआईएसई+ 2024-25 के आँकड़े एक विरोधाभास को उजागर करते हैं: जहाँ जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण पूर्ण नामांकन में गिरावट आ रही है, वहीं स्कूल छोड़ने की दर कम हो रही है और जीईआर में सुधार हो रहा है, जो मज़बूत प्रतिधारण का संकेत देता है। भारत के लिए, आगे की चुनौती सार्वभौमिक पहुँच से कम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, कौशल निर्माण और घटती बाल जनसंख्या के अनुरूप शैक्षिक नीतियों को अपनाने से संबंधित है। नामांकन प्रवृत्तियों में इस महत्वपूर्ण मोड़ को स्कूली शिक्षा में सुधारों को गहरा करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) से तात्पर्य है:

- (क) कुल जनसंख्या की तुलना में स्कूल में नामांकित बच्चों का प्रतिशत।
- (ख) शिक्षा में नामांकित पात्र स्कूली बच्चों का प्रतिशत, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो।
- (ग) किसी विशेष स्तर पर शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों का प्रतिशत।
- (घ) किसी दिए गए स्कूल वर्ष में शिक्षकों और छात्रों का अनुपात।

उत्तर: (ख)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: यूडीआईएसई+ 2024-25 के आँकड़े 3-11 आयु वर्ग में स्कूल नामांकन में लगभग 25 लाख की गिरावट दर्शाते हैं, लेकिन सकल नामांकन अनुपात में सुधार और स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी दर्शाते हैं। इन प्रवृत्तियों के पीछे के कारकों और भारत में शिक्षा नीति पर उनके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (250 Words)

हाल ही में एक चीनी कंपनी द्वारा कृत्रिम गर्भाशय वाले गर्भावस्था रोबोट विकसित करने की झूठी खबर ने भविष्य की प्रजनन तकनीकों पर वैश्विक बहस को फिर से छेड़ दिया है। कृत्रिम गर्भाशय, गर्भाशय प्रत्यारोपण और प्रजनन चिकित्सा में वैज्ञानिक प्रयोग, जो अभी भी विज्ञान कथा के दायरे में हैं, प्रजनन उपचारों की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और नैतिक, चिकित्सीय और सामाजिक प्रश्न उठा रहे हैं।

Beyond science fiction: artificial wombs and real progress of fertility treatments

Gita Aravamudan

According to reports that surfaced on the internet last week, a Chinese firm announced plans to create the world's first pregnancy robot with an artificial womb. It was fake news, and all the major news outlets bought it. Because it made flashy sci-fi headlines especially in a world where anything seems possible with omnipresent Artificial intelligence (AI).

It was fake news, and all the major news outlets bought it. Because it made flashy sci-fi headlines especially in a world where anything seems possible with omnipresent Artificial intelligence (AI).

My book on surrogacy, *Baby Makers*, which came out in 2016 had a chapter called *Virgin Birth and Womb Banks*, where I discussed the possibilities of sexless reproduction and artificial wombs which could be enabled by cutting edge technology.

It sounded then like science fiction. And it still remains in the realm of science fiction. But though we are nowhere near producing an artificial womb which can gestate and nurture a human being, the research in this field has been on-going for quite a few years now.

More than 10 years ago when



Though we are nowhere near producing an artificial womb which can gestate and nurture a human being, the research in this field has been on-going for quite a few years now. ISTOCKPHOTO

I was researching my book, I read about Hung-Ching Liu, Professor of Reproductive Medicine at Cornell University, U.S., who had engineered endometrial tissue by prompting cells to grow in an artificial uterus. Apparently, he was also able to successfully implant and grow the embryo of a mouse. In another experiment, Liu used cultured cells collected from a woman's womb and created an artificial womb using a scaffolding. Inside this womb he planted fertilised embryos left over from IVF cycles. In six days, the eggs implanted in it just as they would in a real womb. But his experiment had to end just 14 days later as

researchers were not allowed to grow foetuses in the lab for more than 14 days. In other parts of the world too, exciting research was going on in this field. In Japan, goat foetuses were grown in a prototype womb. In New South Wales, an artificial womb designed to give birth to live sharks was successfully tested.

Womb replacement surgery

Meanwhile, by 2014, womb replacement surgery had become a reality. Five women from Sweden and 11 from the U.K. had their wombs replaced. Two of the women had wombs donated by their mothers.

The first baby born from a

womb transplant was in Sweden in 2014. Since then, around 135 such transplants have been carried out in over a dozen countries, including the United States, China, France, Germany, India, and Türkiye. Approximately 65 babies have been born as a result of such transplants. Galaxy Care Hospital in India has also achieved success with uterine transplants and has delivered babies from transplanted wombs.

As of now, artificial wombs are being used mainly to nurture preterm babies. The babies are placed in bio bags and float in a liquid mimicking the amniotic fluid found in natural wombs. An artificial placenta, which is connected to the umbilical cord, provides oxygen and nutrients.

Experiments are also on to try and produce eggs and sperm from stem cells.

(Gita Aravamudan is an author and independent journalist who writes on gender issues. gita.aravamudan@gmail.com)

For feedback and suggestions

for 'Science', please write to science@thehindu.co.in with the subject 'Daily page'

वैज्ञानिक विकास

1. कृत्रिम गर्भाशय अनुसंधान

- कॉर्नेल विश्वविद्यालय (अमेरिका): इंजीनियर्ड एंडोमेट्रियल ऊतक, जिससे चूहे के भ्रूण और मानव भ्रूण (14 दिनों तक) प्रयोगशाला में निर्मित गर्भाशय में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं।
- जापान: बकरी के भ्रूण को विकसित करने के लिए प्रोटोटाइप कृत्रिम गर्भाशय का उपयोग किया गया।
- ऑस्ट्रेलिया: शार्क पर कृत्रिम गर्भाशय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- वर्तमान अनुप्रयोग: प्राकृतिक एमनियोटिक द्रव और प्लेसेंटा के कार्यों की नकल करते हुए, समय से पहले जन्मे शिशुओं को सहारा देने के लिए कृत्रिम गर्भाशय "बायो बैग" विकसित किए जा रहे हैं।

2. गर्भ प्रत्यारोपण

- पहला सफल गर्भ प्रत्यारोपण जिसके परिणामस्वरूप जीवित जन्म हुआ: स्वीडन, 2014।
- तब से: दुनिया भर में लगभग 135 गर्भ प्रत्यारोपण हुए हैं, जिससे अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत और तुर्की में लगभग 65 जीवित जन्म हुए हैं।
- भारत: गैलेक्सी केयर अस्पताल ने सफल गर्भाशय प्रत्यारोपण और जन्मों में अग्रणी भूमिका निभाई है।

3. स्टेम सेल प्रयोग

- स्टेम कोशिकाओं से अंडे और शुक्राणु प्राप्त करने के लिए चल रहा शोध, जो जैविक माता-पिता से युग्मकों के बिना प्रजनन को संभव बनाता है।

महत्व और निहितार्थ

1. चिकित्सीय लाभ

- बांझपन के उपचार में क्रांति लाने की क्षमता, विशेष रूप से कार्यात्मक गर्भाशय रहित महिलाओं के लिए।
- सुरक्षित गर्भकालीन सहायता प्रदान करके अत्यधिक समय से पहले जन्मे शिशुओं की जान बचा सकता है।

2. नैतिक चिंताएँ

- प्राकृतिक और कृत्रिम प्रजनन के बीच धुंधली रेखाएँ नैतिक और धार्मिक बहस को जन्म देती हैं।
- "डिज़ाइनर शिशु" और प्रजनन का वस्तुकरण असमानताओं को और बढ़ा सकता है।
- कृत्रिम गर्भाशयों का व्यवसायीकरण होने पर प्रजनन बाजारों में महिलाओं के शोषण का खतरा।

3. क़ानूनी और नियामक आयाम

- वर्तमान वैश्विक सहमति: भ्रूणों को प्रयोगशालाओं में 14 दिनों से ज़्यादा विकसित नहीं किया जा सकता।
- गर्भाशय प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं में दाता और प्राप्तकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नैतिक निगरानी की आवश्यकता होती है।
- भविष्य: कृत्रिम गर्भाशयों और स्टेम-सेल से प्राप्त युग्मकों को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आवश्यकता हो सकती है।

4. सामाजिक और लैंगिक पहलू

- पितृत्व, सरोगेसी और महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है।
- गर्भावस्था के चिकित्सीय जोखिमों को कम करके महिलाओं को सशक्त बना सकता है, लेकिन प्राकृतिक मातृत्व को दरकिनार करने का भी जोखिम है।

निष्कर्ष

- कृत्रिम गर्भाशय अभी भी काफ़ी हद तक प्रायोगिक विज्ञान के दायरे में हैं, लेकिन गर्भाशय प्रत्यारोपण और नवजात बायोबैग पहले से ही प्रजनन चिकित्सा में बदलाव ला रहे हैं। हालाँकि ये तकनीकें बांझपन के इलाज और समय से पहले जन्म लेने वाले बच्चों के लिए आशा की किरण जगाती हैं, लेकिन ये जटिल नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी लेकर आती हैं। भारत के लिए, जहाँ प्रजनन उपचार का विस्तार हो रहा है, प्राथमिकता संतुलित विनियमन, नैतिक सुरक्षा और न्यायसंगत पहुंच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विज्ञान सामाजिक न्याय या गरिमा को कम किए बिना मानवता की सेवा करे।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: गर्भाशय (गर्भ) प्रत्यारोपण, जो हाल ही में चर्चा में रहा है, का मुख्य उद्देश्य है:

- भारत में मातृ मृत्यु दर को कम करना।
- कार्यात्मक गर्भाशय के बिना महिलाओं के लिए प्रजनन विकल्प प्रदान करना।
- गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के कारण क्षतिग्रस्त प्रजनन अंगों को बदलना।
- भ्रूण के आनुवंशिक संशोधन को सक्षम बनाना।

उत्तर: (b)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: कृत्रिम गर्भाशय और गर्भाशय प्रत्यारोपण प्रजनन चिकित्सा में एक अग्रणी स्थान रखते हैं। भारतीय संदर्भ में इनके संभावित लाभों और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (150 Words)

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। 1.4 अरब की आबादी के साथ, चुनौती दोहरी है: वंचित आबादी तक पहुँच का विस्तार करना और बढ़ती लागतों के बीच सामर्थ्य सुनिश्चित करना। आगे का रास्ता एक व्यवस्थित दृष्टिकोण में निहित है जिसमें बीमा को मज़बूत करना, पैमाने का लाभ उठाना, प्राथमिक देखभाल में रोकथाम को शामिल करना, डिजिटल अपनाने में तेज़ी लाना, नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करना और निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

Building health for 1.4 billion Indians

India's health-care system stands at a defining juncture. The task is dual: expand access for the millions who are underserved, while ensuring affordability amid rising costs. This needs an integrated framework, strengthening insurance, leveraging scale, embedding prevention in primary care, accelerating digital adoption, enabling regulatory clarity, and unlocking sustained investment. Through a systemic, interconnected approach, India can build a health-care model that is inclusive, financially viable, and globally aspirational.

Insurance as the foundation of affordability

Pooling risk remains the most effective way to make costly care accessible. Even modest premiums – ₹5,000 to ₹20,000 for individuals or ₹10,000 to ₹50,000 for families – can unlock coverage worth several lakhs, shielding households from catastrophic financial shocks. Yet, penetration remains low: only 15%-18% of Indians are insured, with the premium-to-GDP ratio at 3.7% compared to the global average of 7%. The gap is significant, but so is the opportunity, as gross written premiums already stand at \$15 billion in 2024 and are projected to grow at over 20% CAGR till 2030.

Affordability cannot rest on insurance alone. True impact comes when payers, providers and patients partner, expanding coverage, embracing prevention and making insurance a tool for everyday health security, not just a crisis shield.

India's health-care system has mastered something that the world is only now beginning to appreciate – delivering quality care at extraordinary scale. Where an MRI in the West may handle seven to eight scans a day, in India the same machine manages many times that volume. This ability to stretch resources without diluting quality is not coincidence. It is the product of decades of ingenuity in doctor-patient ratios, workflow design, and infrastructure use.

The next leap is clear: extend this efficiency to India's vast heartland. Tier-2 and tier-3 cities remain underserved, yet they represent the true



Sangita Reddy

is Joint Managing Director, Apollo Hospitals Group

frontier. If India can replicate its urban efficiency in these geographies, it will not just close the access gap. It could set a global benchmark for how scale, innovation and inclusion can reshape health care.

Schemes such as Ayushman Bharat (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, or PM-JAY) have redefined access. Covering nearly 500 million people, with ₹5 lakh a family for advanced care, PM-JAY has enabled millions of cashless treatments in both public and private hospitals. Its impact is visible: timely cancer treatments for beneficiaries have increased by nearly 90%.

Expanding private hospital participation in government-backed schemes is essential to reach the next 500 million. But this must be anchored in fair reimbursements and transparent processes, ensuring viability for providers and real value for patients.

Prevention as the most powerful cost-saver

A study in Punjab revealed a stark reality – even insured families faced catastrophic expenses on diabetes, hypertension, and other non-communicable disease (NCD) outpatient care. The solution is two-fold: redesign insurance to include outpatient and diagnostics, and launch a nationwide push for prevention. But this is incomplete without public participation.

Alongside payers and providers, people must embrace a preventive mindset – controlling risks, staying alert and raising awareness. Every rupee in healthier lifestyles saves multiples in treatment. If schools, employers, communities and citizens rally behind prevention, India can blunt the looming tsunami of NCDs and secure a healthier future.

India was early to adopt telemedicine and is now pushing boundaries with Artificial Intelligence. Tools that detect early signs of sepsis, triage diagnostic reports, or enable remote consultations are already in practice. These innovations not only improve patient outcomes but also optimise the productivity of doctors and nurses.

Digital health is also democratising access.

Remote consultations mean that a cardiologist in a metropolitan city can guide treatment for a patient in a village that is hundreds of kilometres away. Combined with the government's Ayushman Bharat Digital Mission, such innovations could enable universal health records and continuity of care across the country.

Regulation and trust as the missing link

Health-care innovations are promising, but challenges persist. Insurers in New Delhi are considering a 10%-15% premium hike due to pollution-driven respiratory illnesses which shows how environmental factors raise health-care costs. Without safeguards, such pressures could hit affordability for millions. This is where regulation is crucial. The Finance Ministry has urged the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) to strengthen claims of settlement and grievance redress, recognising that trust drives insurance penetration. Without confidence in fair and transparent claims, households will not prioritise health insurance. Robust regulation, paired with fair pricing, is essential to deepen coverage and build confidence.

In 2023, India's health sector drew \$5.5 billion in private equity and venture capital, fuelling digital health, pharmacy networks, and hospitals. But capital remains skewed toward metros. The true test is directing this to tier-2 and tier-3 cities, building primary networks, and training specialists so that growth translates into inclusion.

India's health care is at an inflection point. Insurance must cover everyday care, providers must scale efficiently, prevention must cut long-term costs, and technology must drive access. With aligned investment and bold public-private partnerships, we can design a system that is not episodic or exclusionary, but universal, resilient, and sustainable. Health care must move from being a privilege to becoming every Indian's right.

Health care in India is at an inflection point and must move from being a privilege to becoming every Indian's right

प्रमुख चुनौतियाँ

1. बीमा की कम पहुँच

○ केवल 15-18% भारतीयों ने बीमा कराया है; प्रीमियम-से-जीडीपी अनुपात 3.7% है, जबकि वैश्विक औसत 7% है।

○ वर्तमान स्वास्थ्य कवर बाह्य रोगी और नैदानिक खर्चों के लिए अपर्याप्त है।

2. असमान पहुँच

- शहरी भारत में बुनियादी ढाँचा केंद्रित है, जबकि टियर-2 और टियर-3 शहर अभी भी कम सेवा प्राप्त कर रहे हैं।
- पीएम-जेएवाई के 50 करोड़ लोगों को कवर करने के बावजूद, कई निजी अस्पताल प्रतिपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहे हैं।

3. बढ़ता गैर-संचारी रोगों का बोझ

- मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अन्य गैर-संचारी रोग बीमा के बावजूद परिवारों को स्वास्थ्य पर अत्यधिक खर्च करने पर मजबूर कर रहे हैं।

4. नियामक और विश्वास की कमी

- दावा निपटान में देरी और पारदर्शी प्रक्रियाओं का अभाव परिवारों को बीमा खरीदने से रोकता है।
- पर्यावरणीय कारक (प्रदूषण, जलवायु जोखिम) बीमा कंपनियों को उच्च प्रीमियम की ओर धकेल रहे हैं।

5. निवेश असंतुलन

- 2023 में पीई/वीसी फंडिंग में \$5.5 बिलियन - अधिकांशतः महानगरों में केंद्रित; ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में अपर्याप्त वित्त पोषण।

अवसर और उभरते समाधान

1. वहनीयता की नींव के रूप में बीमा

- वहनीय प्रीमियम (व्यक्तियों के लिए ₹5,000-20,000) के माध्यम से जोखिम पूलिंग परिवारों को वित्तीय झटकों से बचा सकती है।
- उचित प्रतिपूर्ति के साथ सरकारी योजनाओं में निजी अस्पतालों की भागीदारी का विस्तार करने की आवश्यकता।

2. रोकथाम और प्राथमिक देखभाल

- प्रतिक्रियात्मक से निवारक स्वास्थ्य देखभाल मॉडल में बदलाव।
- स्कूलों, नियोक्ताओं और समुदायों को गैर-संचारी रोगों के बोझ को कम करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना चाहिए।

3. दक्षता और पैमाना

- भारत के उच्च-मात्रा, कम-लागत वाली गुणवत्तापूर्ण देखभाल (जैसे, एमआरआई उपयोग, डॉक्टर-रोगी अनुपात) के मॉडल को टियर-2/3 शहरों में दोहराया जा सकता है।
- आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त कमियों को पाट सकता है।

4. डिजिटल परिवर्तन

- निदान, शीघ्र पहचान और दूरस्थ परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन और एआई।
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन राज्यों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाता है।

5. विनियमन और विश्वास

- निष्पक्ष दावों, शिकायत निवारण और पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने में IRDAI की मजबूत भूमिका।
- बीमा प्रणाली में विश्वास से व्यापक पैठ बढ़ेगी।

आगे की राह

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC): बीमा को अस्पताल में भर्ती होने से आगे बढ़कर रोज़मर्रा की बाह्य रोगी और नैदानिक ज़रूरतों को पूरा करना होगा।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी): अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके पहुँच का विस्तार करना।
- टियर-2/3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करना: अस्पतालों के निर्माण, विशेषज्ञों के प्रशिक्षण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए प्रत्यक्ष निवेश।
- एकीकृत निवारक रणनीति: बीमा-संबंधी प्रोत्साहनों द्वारा समर्थित, गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के जोखिमों को कम करने के लिए राष्ट्रीय अभियान।
- सतत वित्तपोषण: प्रीमियम को वहनीय रखते हुए प्रदाताओं के लिए उचित प्रतिपूर्ति और दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष

- भारत की स्वास्थ्य सेवा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगली छलांग के लिए प्रासंगिक संकट-संचालित देखभाल से सार्वभौमिक, निवारक और डिजिटल-प्रथम स्वास्थ्य सेवा की ओर बढ़ना आवश्यक है। बीमा कवरेज, कुशल पैमाने, डिजिटल अपनाने और निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों को मिलाकर, भारत एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कर सकता है जो न केवल 1.4 अरब नागरिकों के लिए समावेशी हो, बल्कि वहनीय, टिकाऊ देखभाल के लिए एक वैश्विक मानक भी हो।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। पहुँच और सामर्थ्य सुनिश्चित करने में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और एक समावेशी एवं टिकाऊ स्वास्थ्य मॉडल के निर्माण हेतु उपाय सुझाइए। (150 Words)

27 अगस्त, 2025 को, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत से आयात पर 50% तक का भारी शुल्क लगा दिया, जिससे कई श्रम-प्रधान निर्यात क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए। इस कदम से झींगा, कपड़ा, आभूषण और कालीन जैसे अमेरिकी बाज़ार पर अत्यधिक निर्भर उद्योगों में तत्काल संकट पैदा हो गया है, साथ ही रसायन, धातु और मशीनरी जैसे मध्यम-प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी अनिश्चितता पैदा हो गई है। यह घटनाक्रम भारत की बाहरी कमज़ोरियों और निर्यात विविधीकरण की तत्काल आवश्यकता, दोनों को उजागर करता है।

Which sectors are worst hit by tariffs?

How high are the new U.S. tariffs on Indian exports? Which sectors are likely to feel the most pain? What has been the immediate impact on shrimp, textiles, and jewellery? Which sectors are likely to face only a modest impact? What short-term support is the government planning?

EXPLAINER

T.C.A. Sharad Raghavan

The story so far:

The 50% tariffs imposed by the U.S. on imports from India came into effect on August 27, sending ripples through the Indian economy and the government. Several sectors, many of them labour-intensive, have the U.S. as a major export destination, and many are already seeing a significant dip in demand. The government is cognisant of this and is devising a plan to support these sectors, at least in the short term.

How do we know which sectors will be worst affected?

The intensity of the impact of tariffs can be arrived at by looking at three metrics in combination: the amount exported to the U.S. in absolute terms, the share of the U.S. in that sector's total exports to the world, and the final tariff that sector is facing.

If a sector exports a large amount to the U.S., the U.S. forms a major part of its total exports, and the tariffs are high, then the pain felt by that sector will likely be high. However, if the U.S. forms a small share in a sector's total exports, then the impact is likely to be limited.

Which sectors are likely to see a severe impact?

According to data from the Ministry of Commerce and Industry, India exported about \$2.4 billion worth of shrimp to the U.S. in 2024-25, making up 32.4% of its total shrimp exports. Earlier, the U.S. only imposed a 10% countervailing tariff on shrimp from India. However, the addition of the 50% tariff now takes this total to 60%.



Major impact: Several sectors, many of them labour-intensive, have the U.S. as a major export destination, and many are already seeing a significant dip in demand. GETTY IMAGES

Reports indicate that exporter purchase prices of shrimp in Andhra Pradesh – the source of the majority of India's shrimp – fell by about 20% following the 25% tariff imposed on August 7. Prices are likely to fall further due to the current 60% tariff.

India exported \$10 billion worth of diamonds, gold, and jewellery to the U.S. in 2024-25, accounting for 40% of total exports in this sector. Tariffs have now risen from 2.1% to 52.1%. Reports from hubs like Surat already show that production cuts are underway. Surat's diamond polishing industry itself employs about 12 lakh people.

One of the worst-hit sectors is likely to be India's textiles and apparel exports sector. These exports to the U.S. stood at \$10.8 billion in 2024-25, with apparel alone accounting for \$5.4 billion. Further, the U.S. accounts for 35% of India's apparel exports. The sector now faces a 63.9% tariff, up from the previous 13.9%.

"Tiruppur exporters are rushing shipments while cancelling new styles," said the Global Trade Research Initiative (GTRI) in its report. "Noida-Gurugram has frozen planned capacity expansions and is considering downsizing, Ludhiana reports a slump in yarn and fabric demand, with working capital under stress, and Bengaluru units are preparing for shift cuts as buyers push for offshore production."

India exported \$1.2 billion worth of carpets to the U.S. in 2024-25, which makes up 58.6% of total carpet exports. Tariffs have increased from 2.9% to 52.9%. Other significantly affected sectors include handicrafts, leather and shoes, furniture and bedding, and agricultural products such as basmati rice, spices, tea, pulses, and sesame.

Which sectors will see a more modest impact?

India's export of organic chemicals to the

U.S. stood at \$2.7 billion. This made up 13.2% of India's total exports. The sector now faces 54% import tariffs, up from the previous 4%. The exporters' body, CHEMEXCIL, and industry bodies have already approached the government for some intervention.

India exported \$4.7 billion worth of steel, aluminium, and copper to the U.S. in 2024-25, about 17% of India's total exports of these metals.

"While the U.S. is not the largest market for Indian metals, it is critical for hundreds of SMEs in the Delhi-NCR engineering belt and eastern foundry hubs," GTRI said.

"The tariff threatens to disrupt jobs in stainless steel, aluminium casting, and copper semi-finished goods, putting severe pressure on small and medium exporters reliant on U.S. orders."

India exported \$6.7 billion worth of machinery and mechanical appliances to the U.S. in 2024-25, making up 20% of its total exports. This sector is also expected to face a drop in demand.

Is the government planning to help these sectors?

Prime Minister Narendra Modi and Commerce and Industries Minister Piyush Goyal have been repeating the 'swadeshi' mantra and asking Indians to 'go vocal for local', so that the economy can reduce its dependence on exports. Apart from this, *The Hindu* reported on August 13 that the government is working on a multi-ministry plan to ease the short-term pain of exporters.

In the medium to long term, the government is working with exporter bodies to diversify their export destinations and make better use of existing free trade agreements. The Reserve Bank of India Governor Sanjay Malhotra has also said that the central bank stands ready to provide whatever help it can.

THE GIST

Severe impact is expected on shrimp, diamonds and jewellery, textiles and apparel, and carpets due to tariffs rising up to 60%, with reports of production cuts, price falls, and downsizing.

Moderate impact will be felt in organic chemicals, metals, and machinery exports, with SMEs and exporters' bodies seeking intervention.

The government is working on a multi-ministry plan, promoting the 'swadeshi' and 'vocal for local' push, while also aiming to diversify export destinations.

प्रमुख रूप से प्रभावित क्षेत्र

- झींगा: अमेरिका को 2.4 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात, जो भारत के झींगा निर्यात का 32% है, अब 60% टैरिफ (10% से ऊपर) का सामना कर रहा है। आंध्र प्रदेश के जलीय कृषि केंद्रों में कीमतें पहले ही लगभग 20% तक गिर चुकी हैं।
- आभूषण और हीरे: 10 अरब डॉलर के निर्यात (अमेरिका को 40% हिस्सा) के साथ, टैरिफ 2.1% से बढ़कर 52.1% हो गए हैं। सूरत का हीरा पॉलिशिंग उद्योग, जिसमें लगभग 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उत्पादन में कटौती की सूचना दे रहा है।

- कपड़ा और परिधान: सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक। 10.8 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात, जिसमें अकेले परिधान का निर्यात 5.4 अरब डॉलर है। अमेरिका भारत के परिधान निर्यात का 35% हिस्सा अवशोषित करता है। टैरिफ अब 63.9% (13.9% से बढ़कर) हो गए हैं, जिससे तिरुपुर, नोएडा, लुधियाना और बेंगलुरु केंद्रों को अपना उत्पादन कम करना पड़ रहा है।
- कालीन: 1.2 अरब डॉलर का निर्यात, 58% अमेरिका को, टैरिफ 2.9% से बढ़कर 52.9% हो गया है।
- अन्य संवेदनशील क्षेत्र: हस्तशिल्प, चमड़ा, फर्नीचर और कृषि उत्पाद (बासमती चावल, चाय, मसाले, दालें, तिल)।

मध्यम रूप से प्रभावित क्षेत्र

- कार्बनिक रसायन: 2.7 अरब डॉलर का निर्यात, 13% अमेरिका को, टैरिफ अब 54%।
- धातु (स्टील, एल्युमीनियम, तांबा): 4.7 अरब डॉलर का निर्यात, 17% अमेरिका को। हालाँकि अमेरिका सबसे बड़ा बाजार नहीं है, लेकिन एनसीआर और पूर्वी फाउंड्री में छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।
- मशीनरी और यांत्रिक उपकरण: 6.7 बिलियन डॉलर का निर्यात, जिसमें अमेरिका का 20% हिस्सा है, घटती माँग का सामना कर रहा है।

सरकारी प्रतिक्रिया

- अल्पकालिक राहत: कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-मंत्रालय समन्वय, रसद को आसान बनाना और बड़े पैमाने पर छंटनी को रोकना।

मध्यम से दीर्घकालिक रणनीति:

- नए व्यापार मार्गों और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से निर्यात विविधीकरण।
- 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत घरेलू माँग को मजबूत करना।
- दबावग्रस्त निर्यातकों के लिए RBI द्वारा वित्तीय सहायता का आश्वासन।
- लघु और मध्यम उद्यमों (SME) और श्रम-प्रधान समूहों को सहारा देने के लिए उद्योग जगत की भागीदारी।

निष्कर्ष

- अमेरिकी टैरिफ वृद्धि भारत की कुछ प्रमुख बाजारों पर निर्भरता और श्रम-प्रधान क्षेत्रों की कमजोरी को रेखांकित करती है। जहाँ नौकरियों और आजीविका की सुरक्षा के लिए तत्काल सरकारी सहायता महत्वपूर्ण है, वहीं यह घटना निर्यात विविधीकरण, उच्च घरेलू मूल्यवर्धन और लचीली व्यापार रणनीतियों की संरचनात्मक आवश्यकता को भी उजागर करती है। इस संकट को मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैकल्पिक बाजारों के निर्माण के अवसर में बदलना भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा।

UPSC Prelims Practice Question

प्रश्न: निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें:

1. झींगा निर्यात
2. वस्त्र एवं परिधान
3. आभूषण एवं हीरे
4. कालीन एवं हस्तशिल्प

उपर्युक्त में से कौन से श्रम-प्रधान क्षेत्र हाल ही में अमेरिकी टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं?

- A.** केवल 1 और 2
- B.** केवल 1, 2 और 3
- C.** केवल 2, 3 और 4
- D.** 1, 2, 3 और 4

उत्तर: A)

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारतीय निर्यात पर हाल ही में अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से आर्थिक और सामाजिक दोनों चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं।" प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा कीजिए और सुझाव दीजिए कि भारत इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकता है।
(250 words)

Page : 08 Editorial Analysis

India's demographic dividend as a time bomb

Nobel laureate Rabindranath Tagore once said, "Don't limit a child to your own learning, for she was born in another time." In the context of India's education system, this quote is particularly resonant today. India's education system is outdated. We are preparing students for jobs that are rapidly disappearing or evolving.

Meanwhile the future of work is being shaped by emerging technologies, led by Artificial Intelligence (AI), being the most disruptive of them all. AI is reshaping how we work and think, with our research suggesting that up to 70% of current jobs, globally, will be impacted, and up to 30% of tasks in many current jobs will get completely automated. A plethora of new jobs related to AI development and implementation are being created as we speak. This technological shift via AI is already changing the world and the job market, whereas the curriculum update cycle in our schools and colleges runs in three-year cycles. This is incremental at best, leading to many students being left behind if we do not up-skill, cross-skill and re-skill them.

India's 'demographic dividend' has long been touted as a key driver of the nation's future growth. With more than 800 million people below the age of 35, the country boasts of having one of the largest youth populations anywhere. This demographic 'asset', however, is increasingly under threat of becoming a 'liability', as the gap between education and real-world skills, and degrees and employability widens. If this gap is not addressed, India's demographic dividend could morph into a demographic time bomb – a paradox at scale.

The stark reality is that while India is producing millions of graduates every year, many of these graduates remain underemployed and are increasingly becoming unemployable. Despite popular belief, this is not merely a problem facing social science or non-STEM (science, technology, engineering and mathematics) students. Over the past decade, data show that 40%-50% of engineering graduates from Indian universities have not been placed in jobs, highlighting the worrying gap between academic education and industry requirements. More and more youngsters are going to college or university, yet employers report increasing difficulty in finding talent with the right skills. Belatedly, educators are acknowledging the problem, with 61% of higher education leaders today agreeing that curricula are not aligned with rapidly changing job market needs.

The mismatch begins in high school

As the AI revolution accelerates, India faces a deepening skills crisis. According to McKinsey, nearly seven out of every 10 Indian jobs are at risk from automation by 2030. This means a massive



Martin Whitehead

is a behavioural economist and former Partner, PwC



Amar Anand Singh

is currently Chief Investment Officer of Auroville Investment Management Limited and Founder of the Auro Group of Companies. He was Managing Director and part of the founding team at Tybourne Capital

India's demographic 'asset' – its large youth population – is in danger of becoming a 'liability' as the gap between education and real-world skills and degrees and employability grows wider

and unprecedented change could be affecting the nation in just the next five years. Of course, it is not all bad news. The World Economic Forum predicts that AI and other new tech will create 170 million new jobs by 2030. The problem is that in the same period, more than half of this number of newly created jobs (92 million) will be displaced. Consequently, skilling must become a critical national priority.

The challenge lies in how Indian youth are entering the workforce. A significant number are doing so with outdated or irrelevant skills. This misalignment begins in high school, where students are largely unaware of the multitude of career paths that exist. A Mindler Career Awareness Survey from 2022 revealed that 93% of Indian students between classes 8 to 12 are aware of only seven career options, most of which are traditional roles such as doctor, engineer, lawyer, or teacher. In contrast, the modern economy offers over 20,000 career paths. Surprisingly, a mere 7% of students report receiving formal career guidance during their schooling years. This lack of awareness leads to millions of our best and brightest, pursuing degrees that do not match their aptitudes or market needs. Do not take our word for it. According to the India Skills Report 2024, more than 65% of high school graduates pursue degrees that are not aligned with their interests or abilities. This alarming reality means that students emerge from their degrees ill-equipped for the rapidly changing job market, further exacerbating India's unemployment crisis.

Digital tools, but analog mindsets

While most students in India now have access to some technology as smartphones have become much cheaper, and the government has also tried to roll out computer and AI labs, most schools still follow traditional, examination-centric curricula. There is limited focus on career exploration or the development of job-ready skills. As a result, students graduate with degrees but lack the practical experience required by employers. In fact, the Graduate Skills Index 2025 produced by Mercer-Mettl found that only 43% of Indian graduates are deemed job-ready. In our experience with interns and fresh graduates, this figure, if anything, underestimates the scale of the problem.

EdTech platforms primarily focus on test preparation and rote learning, rather than career discovery or skill development. Coursera, Udemy and other look-alikes have tried to address this problem, but the certificates obtained from these are becoming increasingly commoditised. School curricula remain disconnected from the evolving job market, leaving students unprepared for the challenges ahead. Only a few State boards and central bodies have introduced career readiness

frameworks, and even fewer integrate emerging career pathways into their curricula.

The Indian government, to its credit, has launched several initiatives that are aimed at bridging the skills gap, the most prominent being the Skill India Mission, which aimed to train over 400 million individuals by 2022. Despite large-scale funding, the mission fell far short of this target. Multiple systemic issues have contributed to this failure: besides the Skill India Mission, an acronym soup of other policies has also been launched which includes the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY), Pradhan Mantri Kaushal Kendras (PMKK), Jan Shikshan Sansthan (JSS), Pradhan Mantri Yuva Yojana (PMYY), Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion (SANKALP), Prime Minister's Internship Scheme, and many others,

What India needs is a cohesive strategy that aligns education and skill development with industry demands. We have undertaken deep research and devised a platform for just that. We are in conversations with NITI Aayog, the Association of Indian Universities (AIU), and the Skill Ministry to translate this solution into reality. Collaboration between the government, private sector and educational institutions will be essential to create a robust ecosystem for skill development.

The decisive decade

India's ambition to emerge as a global digital powerhouse rests on its ability to integrate technology, education and employment into a coherent national framework. India's youth will either be equipped with the skills to thrive in an AI-driven world or be left behind. This is not just an education or employment crisis; it is a crisis where our entire social contract could come undone. The student civil disobedience during the Mandal Commission days in 1990 bear witness to the havoc that youth-led protests can create, escalating into violence, clashes with police, property destruction, and, in some cases, fatalities due to police firings. If India fails to act now, it risks creating a generation of highly literate, even educated but unemployable youth that can become a ticking time-bomb. The World Bank Economic Review has ably captured this paradox at scale in an article by Lant Pritchett, "Where Has All the Education Gone?". The ramifications of such a crisis are dire. The good news is that this is an entirely fixable problem. India must prepare its youth not for the jobs of yesterday, but for the careers of tomorrow. The clock is ticking and it is up to us to convert India's demographic dividend into an asset or a liability.

Ritu Kulshrestha supported the initial stages of the article, specifically with data content and drafting

GS. Paper 01- भारतीय समाज

UPSC Mains Practice Question: "भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश एक जनसांख्यिकीय टाइम बम में तब्दील होने का जोखिम उठा रहा है।" भारत की शिक्षा और कौशल विकास चुनौतियों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (150 words)

संदर्भ:

भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है, जिसमें 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। इस जनसांख्यिकीय लाभांश को लंबे समय से भारत के विकास इंजन के रूप में देखा जाता रहा है। हालाँकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के नेतृत्व में तेज़ी से हो रहे तकनीकी बदलाव, शिक्षा और उद्योग की ज़रूरतों के बीच बढ़ते बेमेल और व्यापक बेरोजगारी के कारण, यह संभावित लाभांश एक जनसांख्यिकीय दायित्व या यहाँ तक कि एक "टाइम बम" में बदल सकता है।

मुख्य विश्लेषण

1. कौशल-रोज़गार योग्यता का अंतर

- भारत हर साल लाखों स्नातक तैयार करता है, फिर भी 40-50% इंजीनियरिंग स्नातक नौकरी के लिए तैयार कौशल की कमी के कारण बेरोज़गार रहते हैं।
- स्नातक कौशल सूचकांक (2025) दर्शाता है कि केवल 43% भारतीय स्नातक ही रोज़गार योग्य हैं।
- नौकरी बाज़ार में तेज़ी से हो रहे बदलावों की तुलना में पाठ्यक्रम अद्यतन चक्र धीमा (हर 3 साल में) है।

2. एआई और उभरती प्रौद्योगिकियों का प्रभाव

- मैकिन्से का अनुमान है कि 2030 तक लगभग 70% भारतीय नौकरियाँ स्वचालन के जोखिम का सामना करेंगी।
- विश्व आर्थिक मंच का अनुमान है कि एआई और नई तकनीकों से 17 करोड़ नई नौकरियाँ पैदा होंगी, लेकिन 9.2 करोड़ नौकरियाँ खत्म हो जाएँगी।
- पुनर्कौशल के बिना, युवा भविष्य के रोज़गार के लिए तैयार नहीं होंगे।

3. शिक्षा और करियर जागरूकता में संरचनात्मक चुनौतियाँ

- पारंपरिक परीक्षा-केंद्रित पाठ्यक्रम स्कूलों में हावी है।
- माइंडलर सर्वेक्षण (2022): अर्थव्यवस्था में 20,000 से ज़्यादा संभावनाओं के बावजूद, 93% छात्र केवल 7 करियर विकल्पों के बारे में जानते हैं।
 - औपचारिक करियर मार्गदर्शन का अभाव (केवल 7% छात्रों को यह मिला)।

4. नीतिगत कमियाँ और अप्रभावी कार्यान्वयन

- स्किल इंडिया मिशन का लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना था, लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।
 - कई खंडित पहलों (पीएमकेवीवाई, संकल्प, पीएमवाईवाई, जेएसएस आदि) में समन्वय का अभाव था।
 - शिक्षा को उद्योग जगत की माँगों के अनुरूप ढालने वाले एक समेकित राष्ट्रीय ढाँचे की आवश्यकता।

5. सामाजिक और राजनीतिक जोखिम

- शिक्षित युवाओं में बढ़ती बेरोज़गारी निराशा और अशांति का कारण बन सकती है।
- ऐतिहासिक समानताएँ: 1990 के मंडल आयोग के विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलनों की संभावना को दर्शाया है।
- बेरोज़गार युवा भारत के सामाजिक अनुबंध को अस्थिर कर सकते हैं।

आगे की राह

- पाठ्यक्रम सुधार: उद्योग और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुरूप निरंतर अद्यतन चक्र।
- प्रारंभिक करियर मार्गदर्शन: स्कूलों में करियर अन्वेषण को एकीकृत करें।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों को कौशल विकास पर सहयोग करना चाहिए।
- उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित अर्थव्यवस्था, डिजिटल सेवाएँ, स्वास्थ्य सेवा, आदि।
- कार्यान्वयन को मज़बूत करें: मौजूदा योजनाओं को एक समन्वित राष्ट्रीय कौशल विकास रणनीति में समेकित करें।

निष्कर्ष

- भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। इसके युवा या तो एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति की नींव बन सकते हैं या फिर निराशा और अशांति का एक टाइम बम। चुनौती संख्याओं की नहीं, बल्कि कौशल की प्रासंगिकता की है। अगर भारत अपनी शिक्षा, तकनीक और रोज़गार रणनीतियों को एक साथ ला पाता है, तो जनसांख्यिकीय लाभांश एक परिसंपत्ति बन जाएगा; अगर ऐसा नहीं हुआ, तो इसके जनसांख्यिकीय आपदा में बदलने का खतरा है। अगला दशक तय करेगा कि भारत किस रास्ते पर चलेगा।